जी. एस. संधवालिया और विकास सूरी, **जे. के सम्मुख**

अनिल कुमार-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

2014 का एल. पी. ए. **No.719**

06 अप्रैल, 2022

भारत का संविधान, **1950-Art.311 (2) (b)**-भारतीय दंड संहिता, **1860-Ss.451,354** और **376B**-हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, **1987-Rls**। **7. 2** (ख) और **3**-शिक्षक द्वारा दो छात्राओं के साथ बलात्कार-इस आधार पर नियमित जांच **की छुट्ट देते हुए** सेवा से बर्खास्त करना कि इससे दो नाबालिग लड़कियों को और मानसिक पीड़ा होगी और सामाजिक कलंक लगेगा कि वे नाबालिग थीं-इस प्रकार, **2012 (2)** एस. सी. टी. **85** में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को देखते हुए, बर्खास्तगी में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया गया कि छात्राओं को विभागीय जांच में **जिरह** की अनावश्यक अनियमितताओं का सामना नहीं करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप शर्मिंदगी, अपमान और जबरदस्ती हो सकती है-इसलिए, सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया।

माना जाता है कि लड़कियों की उम्र और जिन कक्षाओं में वे पढ़ रही थीं, उन पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है और तथ्य यह है कि वे उस समय नाबालिग थीं और बड़ी लड़की केवल दसवीं कक्षा में थी, **उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी** क्योंकि उसकी जन्म तिथि 11.09.1993 है, जबकि छोटी लड़की आठवीं कक्षा में थी। **माननीय** एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा है कि उनके पिता एक मजदूर थे।ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि नियोक्ता के मन में आशंका इस हद तक सच हो गई है कि अपीलकर्ता इस

तथ्य के आधार पर बरी होने के लिए संबंधित गवाहों पर हावी होने में कामयाब रहा है कि गवाहों को प्रतिकूल घोषित किया गया था।

(पैरा 12) ने आगे कहा **गया** कि, यह विवादित नहीं है कि निचली अदालत के समक्ष आए साक्ष्य में भी कि लड़कियां एक समय पर लापता हो गई थीं और उसके बाद प्रारंभिक जांच के अनुसार लौट आई थीं, जिस पर दिनांक 01.05.2010 (अनुलग्नक आर-1) पर भरोसा किया गया है।यह दर्ज किया गया था कि वे स्वयं अपीलकर्ता के कहने पर दिल्ली गए थे, जो उस समय उन्हें धमकी दे रहा था।(पैरा 13) ने आगे यह अभिनिर्धारित किया **गया** कि यदि अपीलकर्ता के वकील का तर्क

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

अब स्वीकार किए जाने के द्वारा, यह लड़कियों को शर्मनाक प्रश्नों के एक और दौर से गुजरने के बराबर होगा, जिससे एक दशक पहले हुई घटना का और अपमान होगा। न्यायाधीश के तराजू कभी भी इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बदसूरत निशान कभी भी ठीक न हों।

आगे कहा कि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जाहिर तौर पर शोर-शराबे के कारण, जो उस समय उठाया गया था और जिसे निचली अदालत ने भी देखा है कि पंचायत में निर्णय लिया गया था कि शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के कदाचार के कारण क्षेत्र में स्थिति उबल रही थी और इस कारण से निदेशक विद्यालय शिक्षा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के साथ पठित 1987 के नियमों के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच को समाप्त करने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था।उक्त निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता है।(पैरा 15)

अनुराग गोयल, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए।

हितेश पंडित, एडिशनल।एजी, हरियाणा।

जी. एस. संधवालिया, जे. (ओरल)

(1) वर्तमान पत्र पेटेंट अपील **माननीय** एकल न्यायाधीश के दिनांक 03.03.2014 के आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके तहत अपीलकर्ता अनिल कुमार द्वारा दायर 2011 के CWP No.8880 को खारिज कर दिया गया था। **माननीय** एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार दिनांकित 03.05.2010 के आदेश को बरकरार रखा (अनुलग्नक पी -2), जिसे निदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा नियमित जांच करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के साथ पठित हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 (संक्षेप में '1987 नियम') के नियम 7.2 (बी) और 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया था।

(2) उक्त आदेश पारित करने के लिए निदेशक स्कूल शिक्षा के **पास** जो तर्क प्रचलित था, वह यह था कि **प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दिनांक 24-04-2010 आई.पी.सी.** की धारा 451,354,376 बी **के तहत पुलिस स्अेशन सदर सिरसा में दर्ज की गठ थी।** जिला शिक्षा अधिकारी से उन लड़कियों के बयानों के साथ एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जो दो बहनें थीं कि अपीलकर्ता अनिल कुमार जो हिंदी शिक्षक थे

उसने बड़ी लड़की के साथ 16.02.2010 और 19.02.2010 पर बलात्कार किया था और छोटी लड़की की शील भंग कर दी थी।लड़कियां दसवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ रही थीं और ऐसे आरोप थे कि टेलीविजन और मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में भी दिखाई गई थीं और यह तथ्य कि वह 19.04.2010 और 20.04.2010 पर आकस्मिक छुट्टी पर रहा था और 22.04.2010 सुबह जल्दी पर चला गया था। जिस तारीख को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके बाद वह बिना अनुमति के जानबूझकर स्कूल से अनुपस्थिति रहे और उन्हें 24.04.2010 पर निलंबित कर दिया गया था।रिपोर्ट के अलावा नैतिक अधमता के जघन्य कृत्यों के बारे में समाचार पत्रों में खबरें आई थीं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया था जिसने न केवल स्कूल की छवि को धूमिल किया था, बल्कि राज्य की छवि को कम किया था, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उन्हें तुरंत सेवा से बाहर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था

ताकि यह एक आंख खोलने वाले उदाहरण के रूप में काम करे।नियमित जांच किए बिना अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए दिया गया तर्क यह था कि यह दो नाबालिग लड़कियों के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनेगा और उन्हें सामाजिक कलंक लाएगा।

(3) अपीलकर्ता के वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कुछ कारण दर्ज किया जाना चाहिए और इसकी अनुपस्थिति में में, आदेश उचित नहीं है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि **माननीय** एकल

न्यायाधीश ने तलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और **अन्य में पारित फैसले पर**

भरोसा करते हुए उक्त आदेश को बरकरार रखते हुए गलती की

1, हममें से एक न्यायमूर्ति जी. एस. संधवालिया द्वारा लिखित और शीर्ष न्यायालय द्वारा जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2 में पारित निर्णय, यह तर्क देने के लिए कि विवादित आदेश और **माननीय** एकल न्यायाधीश का निर्णय न्यायोचित नहीं है और

अपीलकर्ता को विभागीय कार्यवाही में अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।

(4) दूसरी ओर राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया है कि नीचे दिए गए प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश, तथ्यों और परिस्थितियों में उचित हैं और यह

हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। उन्होंने उदयनाथ तिर्की बनाम महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ **मुख्यालय और अन्य** 3 मामले में

पारित बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

[1] 2016 (2) एससीटी 551 [2] (1991) 1 एससीसी 362

अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

769

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

यह भी एक ऐसा मामला था जहां एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया था। बर्खास्तगी आदेश पारित किया गया था क्योंकि अनुशासनात्मक जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था और पीड़ित को अनुशासनात्मक कार्यवाही में अभियोजक गवाह

के रूप में पेश करना संभव नहीं था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जिरह का और आघात होगा।इसलिए, उन्होंने यह प्रस्तुत करने के लिए तर्क का समर्थन किया है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है। इस अदालत की खण्ड पीठ द्वारा **बलबीर सिंह** बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ **पीठ, चंडीगढ़** 4 मामले में पारित फैसले पर भी **भरोसा** रखा गया है।

जिसमें इसी तरह की स्थिति में भी एक छात्रा शामिल थी और बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाले न्यायाधिकरण के आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया गया था कि छात्राओं को विभागीय जांच में जिरह की अनावश्यक अनियमितताओं का सामना नहीं करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप शर्मिंदगी, अपमान और जबरदस्ती हो सकती है, जिसमें निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति बनाम बब्बन प्रसाद यादव 5 पारित फैसले पर भी भरोसा किया गया था।

वही नीचे पढ़ा गया है:- "4. न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जांच करने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था और इसलिए, समाप्ति के आदेश को पारित करने में प्रतिवादी **उत्तरदाताओं द्वारा** अपनाए गए पाठ्यक्रम **का रास्ता** दूषित है। तर्क को अस्वीकार करने का आधार निदेशक, नवोदय विद्यालय समिति बनाम बब्बन प्रसाद यादव, यादव, 2004 (2) स्केल 400 के मामले में दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि केवीएस के लिए शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 81 (बी) के तहत जांच करना अनुचित नहीं होगा क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्षों द्वारा निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है।न्यायाधिकरण विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बब्बन प्रसाद यादव के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित सभी पांच शर्तें वर्तमान मामले में पूरी तरह से संतुष्ट हो गई हैं।2. हमने कुछ **हद** तक आवेदक-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनका विचार है कि तत्काल याचिका योग्यता से रहित है और प्रवेश के योग्य नहीं है।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि वर्तमान मामले में

3 2022 (1) एससीटी 459

4 2012 (2) एससीटी 85

5 (2004) 13 एससीसी 568 770

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

स्कूल की छात्राओं के प्रति आवेदक-याचिकाकर्ता की कुछ गतिविधियों के कारण अनैतिक आचरण के आरोप है। मामले की संवेदनशीलता के लिए आवश्यक था कि ऐसी छात्राओं को विभागीय जांच में जिरह की अनावश्यक अनियमितताओं का सामना नहीं करना पड़े, जिसके परिणामस्वरूप शर्मिंदगी, अपमान और जबरदस्ती हो सकती है।यह भी विवादित नहीं हो सकता कि मामले में प्रारंभिक जांच के बाद संक्षिप्त जांच की गई है और अधिकारियों ने अपना संतोष दर्ज किया है कि आरोपित अधिकारी प्रथमदृष्टया दोषी था।सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 के अनुसार नियमित जांच से सफलतापूर्वक छुटकारा पाने के लिए आयोजित आदेश के लिए उपरोक्त कारणों को पूरा करना आवश्यकता है। बब्बन प्रसाद यादव के मामले (ऊपर) में निर्णय के पैरा 5 में, (ऊपर) माननीय उच्चतम न्यायालय ने जाँच से छूट देने की शक्ति के प्रयोग की प्रस्तावना के रूप में निम्नलिखित पाँच शर्तें निर्धारित की हैं:

"5 न्यायालय के लिए होना यह आवश्यक है वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त नियम के तहत शक्ति के प्रयोग की पूर्व शर्तों को पूरा किया जाए।ये पूर्वशर्तें हैं (1) संक्षिप्त जांच का आयोजन;92) ऐसी संक्षिप्त जाँच में यह निष्कर्ष कि अभियुक्त कर्मचारी नैतिक अधमता का दोषी था; (3) ऐसी संक्षिप्त जाँच के आधार पर निदेशक को संतुष्टि, कि अभियुक्त अधिकारी प्रथमदृष्टया दोषी था; (4) निदेशक को संतुष्टि, कि छात्रों या उनके अभिभावकों को गंभीर शर्मिंदगी या ऐसी अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण जाँच करना समीचीन नहीं था; और अंत में (5) उपरोक्त के समर्थन में कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना।

3. जब उपरोक्त शर्तों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो हम पाते हैं कि आवेदक-याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखने में न्यायाधिकरण

द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है।तदनुसार, तत्काल याचिका योग्यता से रहित होने में विफल हो जाती है, बर्खास्त कर दिया।"

(5) हमारी राय में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित है और हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, हालांकि अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि उसे 09.10.2010 (अनुलग्नक पी-3) को आरोप से भी बरी कर दिया गया था। अपीलकर्ता के साथ दुर्व्यवहार अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य के तथ्यात्मक पहलू को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही देखा जा चुका है।

771

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जो लड़कियों का प्रभारी और स्कूल में हिंदी शिक्षक था। तथ्य यह है कि दुर्भाग्य से उन्हें 26.04.2010 को गिरफ्तारी के बाद, निचली अदालत द्वारा 21-09-2010 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जाहिरतौर पर उसने उक्त तथ्य का लाभ उठाया और न केवल लड़कियों, बल्कि उनके माता-पिता पर भी हावी हो गया, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन भी नहीं किया।दुर्भाग्य से, निचली अदालत ने लड़कियों की चिकित्सा जांच के रिकॉर्ड मांगने की जहमत नहीं उठाई।

(6) वर्तमान मामले में पारित पहले के आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि 11.03.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः-

"अपील की सुनवाई के दौरान, आपराधिक मामले का रिकार्ड तलब किया जो पुलिस स्टेशन सदर सिरसा में दर्ज भा.दं.सं. सी. की धारा 451,354 और 376 के तहत दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट नं.87 दिनांक 24.04.2010 जिसका निर्णय09.10.2010 को अतिरिक्त न्यायधीश सिरसा द्वारा तय किया गया।

हमने उक्त अभिलेख का अवलोकन किया है। उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त (अपीलार्थी) को बरी कर दिया गया है। दोषमुक्ति हो जाने पर कोई टिप्पणी किए बिना, हम पंजीयक

(सतर्कता) को मामले को देखने और प्रशासनिक पक्ष पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।

माननीय ज्ञात अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा का कहना है कि यद्यपि निदेशक अभियोजन ने उक्त दोषमुक्ति **हो** जाने के खिलाफ अपील दायर नहीं करने की राय दी है, फिर भी राज्य सरकार उक्त दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील दायर करने के संबंध में मामले पर पुनर्विचार करेगी और इस संबंध में वह सुनवाई की **अगली** तारीख को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

30 मार्च, 2015 तक स्थगित।"

(7) उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने 2015 के एसएलपी No.8973 को प्राथमिकता दी थी, जिसमें 25.03.2015 **को** एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत वर्तमान अपील पर रोक थी, जिसे 30.09.2016 **को** जारी रखा गया था। इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया और अंततः, 10.05.2016 पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।अपील को केवल 2016 की उक्त सिविल अपील No.10075 को 25.11.2019 (अनुलग्नक ए-6) पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज किए जाने के बाद सूचीबद्ध किया गया था और इस प्रकार, परिणामस्वरूप सुनवाई के लिए आया है।

(8) उक्त आदेश के अनुसरण में, उक्त अधिकारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच की गई है और अब यह मामला इस न्यायालय की सतर्कता और अनुशासनात्मक समिति के समक्ष लंबित है।

हमें उक्त मुद्दे पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंधित अधिकारी को पूर्वाग्रह होगा यदि उक्त तरीके के बारे में कोई टिप्पणी की जाती है जिसमें मुकदमे को अचानक समाप्त कर दिया गया था।

(9) अपीलकर्ता के वकील द्वारा 1987 के नियमों के **उपयुक्त** नियम 7.2 (बी) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) को निम्नानुसार पढ़ा गयाः-

"7. **निश्चित** दंड लगाने से पहले पूछताछ करें।

ए। लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिस व्यक्ति पर ये नियम लागू होते हैं, उसके खिलाफ बड़ा जुर्माना लगाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

बी। जिन आधारों पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उन्हें निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में घटाया जाएगा, जो उस व्यक्ति को लिखित रूप में उन आरोपों के बयान के साथ सूचित किया जाएगा, जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है और किसी अन्य परिस्थिति के बारे में जिसे मामले पर आदेश पारित करते समय विचार में लेने का प्रस्ताव है और उसे एक उचित समय के भीतर लिखित रूप में यह बताने की आवश्यकता होगी कि क्या वह आरोपों की सभी या किसी की सच्चाई को स्वीकार करता है, बचाव के लिए क्या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे देना होगा और क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता है।यदि दंडक प्राधिकारी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है या ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह निर्देश देगा कि एक जांच आयोजित की जाएगी जिस पर उन आरोपों के बारे में सभी साक्ष्यों की सुनवाई की जाएगी जो स्वीकार नहीं किए गए हैं।अभियुक्त व्यक्ति, उप-नियम (3) में वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए, गवाहों से जिरह करने, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने और ऐसे गवाहों को बुलाने का हकदार होगा, जो वह चाहे, बशर्ते कि जाँच करने वाला अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी गवाह को बुलाने से इनकार कर सके। कार्यवाहियों में साक्ष्य और निष्कर्षों के बयान और उनके आधारों का पर्याप्त रिकॉर्ड होगा बशर्ते कि -

i. किसी भी अतिरिक्त आरोप को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी जब वह अपने आरोपित व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप के किसी भी बयान के संबंध में कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है।

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

ii.पूर्वगामी उपनियम के प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां उस आचरण के आधार पर किसी व्यक्ति पर कोई बड़ा जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया था या जहां उसे बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से कम

करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कुछ कारणों से, उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर देना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, या जहां राज्य की सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना समीचीन नहीं माना जाता है।

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

"311. संघ या किसी राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों को बर्खास्त करना, हटाना या उनके पद में कमी करना।

(1) कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के तहत सिविल पद रखता है, उसे उस अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।

(2) उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त या हटाया या **रैंक मे कम** हटाया नहीं

जाएगा, सिवाय उस जांच के जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।बशर्ते कि जहां ऐसी जांच के बाद उस पर ऐसा कोई जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है, वहां ऐसा जुर्माना ऐसी जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर लगाया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगाःबशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगाः-

((क) जहाँ किसी व्यक्ति को उस आचरण के आधार पर बर्खास्त या **रैंक में कम कर**

दिया जाता है या पद से हटा दिया जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे **रैंक में कमी करने का**

अधिकार प्राप्त/प्राधिकारी **संतुष्ट** है कि किसी कारण से, उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए, ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या
774

((ग) जहां, **जैसा भी मामला हो** यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल **इस बात से संतुष्ट** है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

(3) यदि, उपरोक्त किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसी जांच करना यथोचित रूप से **व्यावहारिक** है जैसा कि खंड (2) में निर्दिष्ट किया गया है, तो उस पर ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(10) हमने निचली अदालत के रिकॉर्ड की भी जांच की है। गवाहों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि डॉ. अर्चना अग्रवाल और डॉ. सुनील कुमार के रूप में चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध थे, जिन्हें अभियोजन पक्ष के लिए गवाह के रूप में रखा गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोप 03.09.2010 **को** तैयार किया गया था और सभी चार गवाहों के **गवाही** 09.10.2010 **को** दर्ज **की गई थी** और दुर्भाग्य से इसके तुरंत बाद, उसी तारीख को **उसे बरी** कर दिया गया था।यह स्पष्ट है कि उस समय बर्खास्तगी के आदेश में जो कारण दिए गए थे, वे यह थे कि लड़कियों को और अधिक आघात दिया जाएगा।निचली अदालत बड़ी लड़की की मेडिको लीगल रिपोर्ट का भी उल्लेख करने में विफल रहा, जो यह दिखाने के लिए आगे बढ़ेगी कि बलात्कार की शिकार बड़ी लड़की के हाइमेन में एक पुराना **ठीक हुआ घाव** मौजूद था और योनि ने दो उंगलियों को स्वीकार किया।

(11) बब्बन प्रसाद यादव (ऊपर) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उलट दिया, जिसमें **समाज** के शिक्षकों की सेवाओं को विभागीय जांच किए बिना समाप्त कर दिया गया था, जो इसी आधार पर था कि यह लड़की और उसके माता-पिता के लिए गंभीर शर्मिंदगी का कारण बनेगा।न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों के मामले को खारिज कर दिया था, जबकि उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की नियमित जांच करने का अवसर दिया था।तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय को संतुष्ट करना है कि उक्त नियमों के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सभी पूर्व शर्तों को संक्षिप्त जांच के उद्देश्यों के लिए पूरा किया गया था।इस तरह की संक्षिप्त जांच के आधार पर संतोष **व्यक्त किया गया** कि आरोपित अधिकारी प्रथमदृष्टया दोषी था और लड़कियों और उनके अभिभावक

को समर्थन में लिखित रूप में कारण दर्ज करने में गंभीर शर्मिंदगी के कारण जांच करना समीचीन नहीं था, सभी पूर्व शर्तों को पूरा करेगा।उक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"7. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले को उलटने में गलती की है।पहले उद्धृत नियम स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति से संबंधित है जो **वर्तमान मामले** में प्राप्त होती है।

775

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

नियम चुनौती के दायरे में नहीं है। न्यायालय के लिए केवल यह **इस बात से संतुष्ट है** कि उक्त नियम के तहत शक्ति के प्रयोग की पूर्व शर्तों को पूरा किया जाए।ये पूर्व शर्तें हैं:(1) **एक संक्षिप्त जांच करना** (2) ऐसी संक्षिप्त जांच में यह निष्कर्ष निकालना कि आरोपित कर्मचारी नैतिक अधमता का दोषी था;

(3) ऐसी संक्षिप्त जाँच के आधार पर निदेशक की संतुष्टि कि अभियुक्त अधिकारी प्रथमदृष्टया दोषी था;

(4) निदेशक **की संतुष्टि** कि छात्र या उसके अभिभावकों को गंभीर शर्मिंदगी या ऐसी अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण जांच करना समीचीन नहीं था और अंत में; (5) उपरोक्त के समर्थन में **कारणों को** लिखित रूप में **दर्ज करना**।"

(12) वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, निदेशक बर्खास्तगी का आदेश पारित करते हुए इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इससे छात्राओं को शर्मिंदगी होगी। लड़कियों की उम्र और जिन कक्षाओं में वे पढ़ रही थीं, उन पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है और तथ्य यह है कि वे उस समय नाबालिग थीं और बड़ी लड़की केवल दसवीं कक्षा में लगभग 17 वर्ष की थी, क्योंकि उसकी जन्म तिथि 11.09.1993 है, जबकि छोटी लड़की आठवीं कक्षा में थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी देखा है कि उनके पिता एक मजदूर थे।ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि नियोक्ता के मन में आशंका इस हद तक सच हो गई है कि अपीलकर्ता इस तथ्य के **आधार पर बरी होने के लिए संबंधित गवाहों पर हावी हाने में कामयाब रहा है।**

(13) यह विवादित नहीं है कि निचली अदालत के समक्ष आए साक्ष्य में भी कि लड़कियां एक समय पर लापता हो गई थीं और उसके बाद प्रारंभिक जांच के अनुसार लौट आई थीं, जिस पर दिनांक 01.05.2010 (अनुलग्नक R-1) पर भरोसा किया गया है।यह दर्ज किया गया था कि वे स्वयं अपीलकर्ता के कहने पर दिल्ली गए थे, जो उस समय उन्हें धमकी दे रहा था।इस तथ्य के कारण कि जब वे वहां पहुंचे, तो वे उनसे मिल नहीं सके और उसके बाद वे दूसरों की मदद लेकर वापस आ गए और उस समय उन्हें बरामद कर लिया गया था।

(14) यदि अपीलकर्ता के वकील के तर्क को अब स्वीकार किया जाता है, तो यह लड़कियों को शर्मनाक प्रश्नों के एक और दौर द्वारा गुजरने के बराबर होगा, **जिससे उन्हें और अधिक अपमानित होना पड़ेगा।**

एक घटना जो एक दशक पहले हुई थी।न्यायाधीश के तराजू कभी भी इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बदसूरत निशान कभी भी ठीक न हों। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि सुखबीर सिंह के मामले (ऊपर) में समन्वय पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी पूरी तरह से लागू होगा।

(15) तलविंदर सिंह के मामले (उपरोक्त) में पारित निर्णय किसी भी तरह से अपीलकर्ता के वकील की मदद नहीं करेगा क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक परिवीक्षाधीन की बर्खास्तगी भा.दं.सं. की धारा 376 और 506 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर **की गई** थी और यह वह मामला नहीं था जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत विभागीय जांच को समाप्त कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, विभागीय जांच करने की स्वतंत्रता के साथ आदेश को दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि यह एक दंडात्मक आदेश के बराबर होगा। जसवंत सिंह के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि विभागीय जांच और अन्य आसपास की परिस्थितियों को आयोजित करने के लिए संतुष्टि और **व्यवहारिकता** के प्रश्न के समर्थन में कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आदेश पारित करने के समय उचित व्यवहार्यता का प्रश्न

मौजूद होगा। इस प्रकार स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा **व्यवहारिकता** का सही आकलन किया गया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जाहिर तौर पर शोर-शराबे के कारण, जो उस समय उठाया गया था और जिसे निचली अदालत ने भी देखा है कि पंचायत में निर्णय लिया गया था कि शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के कदाचार के कारण क्षेत्र में स्थिति उबल रही थी और इस कारण से निदेशक विद्यालय शिक्षा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के साथ पठित 1987 के नियमों के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच को समाप्त करने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था।उक्त निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता है और इसलिए, **माननीय** एकल न्यायाधीश के आदेश को किसी भी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता है।(16) नतीजतन, हमारी राय है कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।सभी लंबित नागरिक विविध आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक : गीता